दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

जुलाई 2022 (संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- मुख्यमंत्री को टास्क फोर्स ने सौंपा प्रतिवेदन 3
- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम संधारण के लिये दिये विस्तृत निर्देश 4
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित 4
- एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में मध्य प्रदेश छठे स्थान पर 5
- पुलिसकर्मियों को पुनः मिलेंगे 'रुस्तमजी अवार्ड' 5
- विश्वस्तरीय हार्निया सम्मेलन 6
- केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कारों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का चयन 6
- खनिज विकास में सक्रिय योगदान के लिये मध्य प्रदेश को दो श्रेणी में मिला प्रथम और द्वितीय पुरस्कार 7
- प्रदेश में पहली बार पाइल फाउंडेशन पर बने टावर्स से हुई विद्युत आपूर्ति 7
- उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नैक से सर्वोच्च A++ ग्रेड 8
- मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता, 2022 8
- मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 9
- मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन 9
- सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना 10
- मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में संशोधन 10
- गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन 11
- 'उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047' समारोह 11
- देश का पशुसखी प्रशिक्षण 'A-HELP' कार्यक्रम 12
- जल जीवन मिशन में 11 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएँ मंज़ूर 12
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर 13
- मध्य प्रदेश को मिला 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य' का अवार्ड 13
- बुरहानपुर बना देश का पहला 'हर घर जल' सर्टिफाइड ज़िला 14
- श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह 14
- जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ 15
- तेंदूपत्ता संग्रहण 15
- यूथ महापंचायत 16
- जल जीवन मिशन में 1142 जल-प्रदाय योजनाएँ और शामिल हुईं 16
- प्रदेश का पहला 200 MVA ट्रांसफार्मर दमोह में ऊर्जीकृत 17
- राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को 'बेस्ट एंप्लायर ब्रांड अवार्ड' 17
- प्रदेश को मिला नया कर्माझिरी अभयारण्य 17
- शिवपुरी की सांख्य सागर झील रामसर साइट में शामिल 18
- वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इंडिया अवार्ड 18
- एमपीकिसान ऐप 19
- करोंद मंडी में बनेगा एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम 20
- 'गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग' 20
- ज़िलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट का विमोचन 21
- आईटीसीटीए कॉन्क्लेव चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश ने जीते 2 अवार्ड 21

नोट :

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री को टास्क फोर्स ने सौंपा प्रतिवेदन

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को मध्य प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये गठित टास्क फोर्स की प्रमुख प्रो. शमिका रवि ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अंतिम प्रतिवेदन सौंपा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रही प्रो. शमिका रवि की अध्यक्षता में गत जनवरी माह में टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने निर्धारित अवधि 30 जून को रिपोर्ट सौंपी है।
- टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिलेगी।
- नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अच्छा कार्य किया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश ने टास्क फोर्स का गठन कर विशेष पहल की।
- टास्क फोर्स के प्रतिवेदन में सात अध्याय शामिल हैं। इनमें पोषण की भूमिका, स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों पर नजर रखना, स्वास्थ्य की देखभाल और संसाधनों के अध्ययन, शिशुओं और माताओं की देखभाल में सुधार, वर्तमान स्थिति और पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय और सुशासन एवं अन्य उपायों से इस क्षेत्र में सुधार के अध्याय शामिल हैं।
- प्रतिवेदन में बच्चों में कुपोषण की समाप्ति और मातृ-शिशु कल्याण के क्षेत्र में अच्छे परिणामों के लिये भौतिक अधोसंरचना और संसाधनों की कमी दूर करने, शिशुओं के पूरक आहार, नियमित टीकाकरण, रोगों की रोकथाम, ब्लड बैंक सुविधाओं का विस्तार, नवजात शिशुओं के लिये रेफरल व्यवस्था और परिवहन सुविधा से संबंधित सुझाव भी शामिल हैं।
- इसके अलावा आँगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार देने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन-सहयोग से संचालित अभियान का उल्लेख है।
- मध्य प्रदेश में मातृ-मृत्यु दर 5.8 प्रतिशत की दर से घट रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.5 है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 0.6% की दर से घट रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 3.8 प्रतिशत है।
- टास्क फोर्स ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जो निम्न हैं-
  - शासन स्तर पर नियमित समीक्षा- मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की समग्र व्यवस्था में सुधार के लिये कमियों को समाप्त करने में नियमित समीक्षा उपयोगी है।
  - भौतिक अधोसंरचना और संसाधन- यह प्रतिवेदन एक ऐसा रोडमेप प्रदान करता है। इसमें इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के साथ निवारक मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने (Ending Preventable Maternal Mortalitay) जैसे सुधार ढाँचे और पैकेज शामिल हैं। प्रतिवेदन में जनसंख्या के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता का विश्लेषण भी किया गया है।
  - पोषण- प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुपोषण माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। रक्ताल्पता चिंतनीय है। कुपोषण के निर्धारकों के लिये यूनिसेफ के सुझाव अनुसार हस्तक्षेप करते हुए अच्छे परिणाम लाने का प्रयास किया जाए। सुपोषित आहार के सेवन के साथ ही टीकाकरण के माध्यम से रोगों की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा, पूरक आहार व्यवस्था और उससे संबंधित प्रचार पर जोर दिया गया है।

नोट :

- वित्त व्यवस्था- मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले व्यय के संबंध में प्रतिवेदन में समाज के निचले तबके के लिये सहायता बढ़ाने, परिवार स्वास्थ्य खाते के रूप में ओपीडी देखभाल के लिये वित्तीय सहायता का परामर्श दिया गया है। प्रतिवेदन में हेल्थ आउटकम फंड बनाने का सुझाव भी दिया गया है।
- डेटा का उपयोग- प्रतिवेदन में डेटा आर्किटेक्चर में सुधार में डेटा प्रविष्टि, बैकएंड सत्यापन और समस्याओं की यथा समय पहचान को आवश्यक बताया गया है। अनमोल, समग्र, संपर्क और पोषण ट्रेकर; यह सब डेटा पोर्टल मार्गदर्शी हैं। इनसे राज्य शासन लाभार्थियों को मिलने वाली स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का डेटा सुरक्षित रखने और उसका उपयोग योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने में कर रहा है। प्रतिवेदन में डेटा सिस्टम की वर्तमान चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

- टास्क फोर्स ने विभिन्न सुधारों के लिये विशिष्ट सिफारिशें की हैं, जो नागरिक स्वास्थ्य और पोषण के लिये बेहतर सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करती हैं।

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम संधारण के लिये दिये विस्तृत निर्देश

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये उपयोग में आने वाली ईवीएम के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास ईवीएम पहुँचाने से लेकर मतगणना के पश्चात् इनका संधारण कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिये हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और मतदान केंद्र, मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग-रूम तक ईवीएम मशीनों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये।
- राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने यह भी कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन के लिये आवंटित ईवीएम के समस्त ट्रकों को चयनित अस्थाई ईवीएम स्ट्रांग-रूम में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विहित रीति से संधारित करना होगा। प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के प्रयोजन के लिये प्रदाय की गई ईवीएम को स्ट्रांग-रूम से पृथक् कक्ष, जो कि उसी भवन में हो, आरक्षित कर संधारित किया जाएगा।
- आरओ रेंडमाइजेशन में आवंटित मतदान केंद्र तथा वार्ड रिज़र्व सह कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम को कमीशनिंग के लिये निकालते समय स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति से बोला जाएगा।
- कमीशनिंग के बाद मतदान केंद्र तथा वार्डवार रिज़र्व के लिये तैयार की गई ईवीएम को यथा-निर्धारित अस्थाई स्ट्रांग-रूम में संधारित कर विहित रीति से स्ट्रांग-रूम को सील किया जाएगा।
- कमीशनिंग के दौरान नॉन-वर्किंग पाई गई ईवीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर के पास शेष कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम, जो कि मतदान के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, को स्ट्रांग-रूम से पृथक कक्ष, जिसमें प्रशिक्षण एवं जन-जागरूता के लिये आवंटित ईवीएम को भी रखा जाएगा, में संधारित किया जाएगा।
- सामग्री वितरण दिवस पर मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र से संबंधित ईवीएम तथा सेक्टर/ज़ोनल मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित सेक्टर की वार्डवार रिज़र्व ईवीएम प्रदाय करने के लिये स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति अनुसार खोला जाएगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के 2 शहरों- इंदौर एवं भोपाल में होने वाली जी-20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास पर उनके सत्कार, आवास, सुरक्षा-व्यवस्था के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- समन्वय समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, गृह, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन को सदस्य सचिव एवं नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक की अवधि में भारत जी-20

एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में मध्य प्रदेश छठे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में मध्य प्रदेश पूरे देश में छठवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में मध्य प्रदेश 786 स्कोर के साथ छठे स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा, तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

पुलिसकर्मियों को पुनः मिलेंगे 'रुस्तमजी अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को 'रुस्तमजी अवार्ड' पुनः प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को 3 श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जिनमें 50 हज़ार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि शामिल होगी।

नोट :

- नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा।
- पुरस्कार की 'परम विशिष्ट' श्रेणी में 5 पुरस्कार 5-5 लाख रुपए, 'अति विशिष्ट' श्रेणी में 6 पुरस्कार 2-2 लाख रुपए तथा 'विशिष्ट' श्रेणी के 50-50 हज़ार रुपए के 50 पुरस्कार के साथ प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि रुस्तमजी अवार्ड प्रदेश में दो साल से बंद था। इस अवार्ड के अंतर्गत तीन श्रेणियाँ होती हैं। इसमें परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के लिये नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

विश्वस्तरीय हार्निया सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

9 से 10 जुलाई, 2022 तक राजधानी के जहाँनुमा पैलेस में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा एवं हार्निया सोसायटी ऑफ इंडिया का दोदिवसीय विश्वस्तरीय हार्निया सम्मेलन हुआ, जिसका शुभारंभ 9 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया था।

प्रमुख बिंदु

- इस दोदिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 500 से अधिक डॉक्टर एवं चिकित्सा छात्र शामिल हुए। सम्मेलन में अहमदाबाद में रोबोट के जरिये की जाने वाली सर्जरी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।
- इस अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 'मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन' की भी शुरुआत की गई है। यह मिशन शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
- इस मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुँचाया जा रहा है।
- मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ मेडिकल इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इन्क्यूबेशन सेंटर को विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों को नए चिकित्सा उपकरणों पर शोध एवं उन्हें विकसित करने का अवसर मिलेगा।
- मंत्री ने कहा कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने उद्देश्य से देश के विभिन्न शासकीय एवं निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों के साथ एमओयू कर ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी के विभिन्न सर्जिकल प्रोसिजर में मेडिकल रोबोट के उपयोग के लिये ट्रेनिंग दी जाएगी।
- मध्य प्रदेश में थ्रीडी प्रिंटिंग के उपयोग से प्रोस्थेसिस के विकास, दाँत, हड्डियों एवं विभिन्न अंगों की विशिष्ट बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिकृतियों के निर्माण कर शल्य क्रिया में उपयोग किया जाएगा, जिससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कारों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का चयन

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खनिज विकास के लिये अपनाई जा रही नीतियों और उल्लेखनीय कार्यों हेतु नई दिल्ली में होने वाले 6वें नेशनल कॉनक्लेव में पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 2 श्रेणी में क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही राज्य शासन को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 से केंद्रीय अधिनियम में किये गए संशोधन के बाद मुख्य खनिजों के ब्लॉकों को नीलामी के माध्यम से आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

नोट :

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस दिशा में शीघ्रता से कार्य करते हुए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर अब तक 52 मुख्य खनिजों के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है। इनमें हीरा, चूना-पत्थर, मैंग्नीज़, बॉक्साइट, आयरन ओर, रॉक फास्फेट आदि खनिज के ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से 27 खनिज ब्लॉक सफलता से नीलाम हो चुके हैं।
- नीलामी के बाद खदान संचालित होने पर आगामी 50 वर्षों में राज्य शासन को 47 हज़ार 219 करोड़ रुपए का राजस्व संभावित होगा। प्रदेश में आगामी चरण में मुख्य खनिजों के 27 ब्लॉकों की नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है।
- गौरतलब है कि नई दिल्ली में होने वाले 6वें नेशनल कॉनक्लेव का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी करेंगे। इस नेशनल कॉनक्लेव में खनिज नीलामी प्रक्रिया को सफलता से क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

खनिज विकास में सक्रिय योगदान के लिये मध्य प्रदेश को दो श्रेणी में मिला प्रथम और द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में छठे नेशनल कॉनक्लेव में मध्य प्रदेश को दो श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से नवाज़ा गया। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार के लिये दो श्रेणियाँ निर्धारित की गई थीं, जिनमें मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 3 करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वहीं उत्खनन, नीलामी, खदानों के संचालन में पहल करने और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 2 करोड़ रुपए के दूसरे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को खदानों की सफल नीलामी के लिये 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मिले।
- मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जिसे 7 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में मिली है।

प्रदेश में पहली बार पाइल फाउंडेशन पर बने टावर्स से हुई विद्युत आपूर्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश में पहली बार अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार में पाइल फाउंडेशन पर अति उच्च दाब टावरों से विद्युत आपूर्ति की है।

प्रमुख बिंदु

- लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी ने 132 केवी बुधनी मोहासा (बावई) डीसीडीएस (डबल सर्किट डबल स्ट्रिंगिंग) लाइन के 5 किलोमीटर लंबाई के बीच में चार टावरों के निर्माण में तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- ये टावर मोहासा ग्राम के पास से गुजरने वाली तवा नदी में निर्मित किये गए हैं। कुल 9 किलोमीटर की ये लाइन हाल ही में ऊर्जीकृत की गई।
- कंपनी के सामने पूर्व में भी नदी, तालाब, नाले आदि क्रास करवा कर अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। प्राय: नदी के दोनों छोर पर लंबे स्पान के साथ इनका निर्माण किया जाता था। इससे निर्माण के साथ रख-रखाव में भी दिक्कत आती थी। इस नई तकनीक को अपनाने से अब नदी के अंदर ही पाइल फाउंडेशन बनाकर इन टावर्स का निर्माण किया गया है।
- कंपनी के योजना एवं रूपांकन संकाय के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कंपनी द्वारा पहली बार उपयोग में लाई जा रही यह तकनीक ट्रॉंसमिशन लाइन निर्माण के लिये मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिये कंपनी ने विशेष डिजाइन के फाउंडेशन तैयार करवाए हैं।
- यह तकनीक जलमग्न और असमान भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य को काफी लचीलापन प्रदान करती है, जिससे लाइनों के निर्माण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन और बाद में रख-रखाव में आसानी रहती है।

नोट :

उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नैक से सर्वोच्च A++ ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल (नैक) में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पूरे देश में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में हैं। इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है। शेष सभी निजी महाविद्यालय हैं।
- माधव विज्ञान महाविद्यालय को 58 सीजीपीए प्राप्त हुआ है, जो अब तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त हुए अंकों में उच्चतम है।
- प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि नैक द्वारा पूर्व में महाविद्यालय की ग्रेडिंग गलत की गई थी। नैक द्वारा महाविद्यालय के पीएचडी होल्डर प्रोफेसर्स और गेस्ट फैकल्टी की गिनती गलत की गई थी। महाविद्यालय द्वारा अपील की गई, जिसके परीक्षण के बाद महाविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है।

मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता, 2022

चर्चा में क्यों ?

14 जुलाई, 2022 को प्रमुख सचिव, पर्यटन और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को प्रदेश के पर्यटन से परिचित कराने एवं पर्यटन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 'मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता, 2022' आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा पर्यटन विकास निगम, ज़िला प्रशासन और जिला पुरातत्त्व पर्यटन और संस्कृति परिषद के सहयोग से आयोजित की जा रही है।
- इस प्रतियोगिता से विद्यार्थी प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक रंगों, स्थानीय कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों और पर्यटन महत्त्व की संभावनाओं आदि से परिचित होंगे।
- प्रतियोगिता से बच्चों में पर्यटन के लिये मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति आकर्षण के साथ पर्यटन संबंधी जानकारी बढ़ेगी।
- प्रतियोगिता में शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
- प्रतियोगिता की विजेता और उप-विजेता टीमों को पर्यटन निगम के होटल्स के टूर पैकेज सहित प्रमाण-पत्र और मेडल दिये जाएंगे। पर्यटन बोर्ड द्वारा 2016 से कोविड काल को छोड़कर प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
- पर्यटन क्विज प्रतियोगिता दो स्तर पर होगी। पहले चरण में ज़िलास्तरीय प्रतियोगिता 24 अगस्त को होगी। ज़िलास्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 3 सदस्यीय टीम का चयन प्रतियोगिता से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय स्तर पर करेंगे।
- हर ज़िले की प्रथम तीन विजेता टीमों को 2 रात और 3 दिन तथा तीन उप-विजेता टीमों को एक रात और 2 दिन पर्यटन विकास निगम के होटल में नि:शुल्क ठहरने का कूपन दिया जाएगा। इसमें पर्यटन स्थल तक आने-जाने, भोजन, स्थानीय भ्रमण आदि का व्यय शामिल होगा। ज़िला स्तर पर पहले स्थान पर आई टीम दूसरे चरण में राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेगी।
- ज़िलास्तरीय प्रतियोगिता दो चरण में होगी। पहले चरण में लिखित प्रश्नोत्तरी और दूसरे चरण में ऑडियो-विजुअल प्रश्न शामिल होंगे। लिखित प्रश्नोत्तरी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 6 टीमों को ऑडियो-विजुअल चरण में प्रवेश दिया जाएगा।
- दोनों चरण में प्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन से संबंधित परिक्षेत्र, कला, संवर्धन, अध्यात्म, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं प्रदेश में फिल्मांकित फिल्म आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। 'आजादी का अमृत महोत्सव' में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रश्न भी शामिल किये जाएंगे।

नोट :

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदान की जाए।
- योजना से सिकलसेल रोगियों की रुग्णता और मृत्यु-दर को कम करने तथा हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने के लिये जेनेटिक काउंसलिंग, सिकलसेल एनीमिया, थैलीसिमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी विकास हेतु समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन जून 2021 में किया गया था। इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 में क्रियान्वित होगी।
- मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 116 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के विभिन्न विभाग में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये कुल 134 पी.जी. सीट्स की वृद्धि होगी।
- मंत्रिपरिषद ने भारत-ओमान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग से एम.ओ.यू. के अनुसार फर्स्ट राइट ऑफ रिफयूजल के अधीन 19 नवंबर, 2020 से 5 वर्षों तक नेफ्था के उपयोग एवं ट्रेडिंग की सहमति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद द्वारा सतना ज़िले की दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 227 करोड़ 56 लाख रुपए सिचाई क्षेत्र 7,200 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- परियोजना से सतना ज़िले की मझगवाँ तहसील के 15 ग्रामों के 7200 हेक्टेयर रकबे में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा प्रेशराइज्ड पद्धति से रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिये आवश्यक जल उपलब्ध होगा।

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन विकसित/विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिये नवीन मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 संशोधित करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें कंडिका 12(ii) स में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से होने के साथ ही राजस्व में बढ़ोत्तरी हो, इसके लिये 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के स्थान पर 'ई-बिडिंग' प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- कंडिका 12(ii) (द), कंडिका 13(ii) कंडिका 13(III), कंडिका 13(अ) मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवा के अनुसार आशय-पत्र, आवंटन आदेश, पट्टाभिलेख निष्पादन, आधिपत्य आदि की समय-सीमा में संशोधन किया गया है।
- कंडिका 13(vii) चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भू-खंड के लिये किश्तों में भुगतान करने हेतु प्रावधान किया गया है।
- कंडिका 19(ब) (II) हस्तांतरण प्रकरणों में 25 प्रतिशत निवेश राशि के साथ न्यूनतम राशि 50 करोड़ रुपए के विकल्प को शामिल किया गया एवं प्रस्तावित परियोजना में किये गए निवेश की स्थिति अनुसार पृथक्-पृथक् हस्तांतरण शुल्क का प्रावधान किया गया है।
- कंडिका 20 को पुनरीक्षित करते हुए कंडिका 20(अ) एवं 20(ब) किया गया है। कंडिका 20(अ) में कार्यरत् इकाइयों की अनुपयोगी भूमि के हस्तांतरण के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल को 500 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर एवं कंडिका 20(ब) में बंद इकाइयों की अनुपयोगी भूमि के विभाजन एवं हस्तांतरण के लिये प्रावधान किया गया है।

नोट :

- कंडिका 24(अ) भू-खंड का समर्पण किये जाने की स्थिति में प्रत्याजी के साथ विकास शुल्क वापसी संबंधी प्रावधान को स्पष्ट करते हुए लघु उद्योग के प्रकरण में 6 वर्ष की समयावधि के बाद तथा मध्यम एवं बृहद् उद्योग के प्रकरण में 7 वर्ष के बाद परंतु 9 वर्ष के पूर्व समर्पण करने पश्चात् भी प्रब्याजी राशि वापस करने का प्रावधान किया गया है।
- कंडिका 34 उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन की अधिकारिता संचालक मंडल को प्रत्यायोजित की गई है।

सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत एप्लीकेशंस/डाटा की सुरक्षा के लिये सुरक्षा संचालन केंद्र (Security Operations Centre) स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर (MPSDC) संचालित है।
- स्टेट डाटा सेंटर में विभिन्न विभागों के संचालित/संधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एवं उनसे संबंधित संवेदनशील तथा अन्य डाटा की साइबर सुरक्षा के लिये राज्य में एक सुरक्षा संचालन केंद्र का संचालन प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता मॉडल पर संचालित किया जाएगा।
- सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एमपीएसईडीसी) के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर (MPSDC) में राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रेस्पॉन्स ऑपरेशन सेंटर CSIRT को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करेगा।
- सुरक्षा संचालन केंद्र] नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (NOC) के समान ही आईटी ऑपरेशन टीम की एक इकाई है, जो नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (NOC) से सहयोग कर क्रियान्वित रहती है।
- सुरक्षा संचालन केंद्र के सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आई.टी. सुरक्षा तंत्र अधो-संरचना और उसके ऑपरेशन के कार्य निष्पादित करते हैं।
- नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (NOC) के साथ एस.ओ.सी. (SOC) द्वारा भी इंफ्रा टीम के आदेशों का दैनंदिन पालन करते हुए आईटी सुरक्षा के विभिन्न लक्ष्य की पूर्ति करेगा।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर में एप्लीकेशंस एवं एप्लीकेशन होस्ट संबंधी गंभीर जोखिमों से बचने में सुरक्षा संचालन केंद्र सहायक के रूप में कार्य करेगा।

मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा खनिज साधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को रखा जाएगा। बोर्ड एवं कार्यकारी समिति में सदस्य के रूप में लोकसभा तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के साथ राज्यसभा के सदस्य को भी शामिल किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में वर्तमान में जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि का नियम 13(2)(ड) अनुसार राज्य खनिज निधि में अंतरित करने का प्रावधान है।

नोट :

- भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य खनिज निधि का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है, अत: पूर्व में जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत राज्य खनिज निधि में जमा राशि का उपयोग किये जाने के लिये नियमों में प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में किये गए हैं। प्रतिष्ठान के उद्देश्य अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में विविध विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर सृजित हो सकेंगे।

गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में नियमों में ई-निविदा से उत्खनन पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अब ई-निविदा से उत्खनि पट्टा एवं समेकित अनुज्ञप्ति पृथक्-पृथक् आवंटित करने का नियमों में संशोधन किया गया है।
- निजी भूमि में वर्तमान नियम में अनुसूची-पाँच के उत्खनन पट्टा भूमि-स्वामी अथवा उसके सहमति धारक को आवंटित करने का प्रावधान है। वर्तमान प्रावधान में उत्खनन पट्टा ग्रांट करने से पूर्व भूमि-स्वामी को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का कार्य करना भी अनिवार्य किया गया है।
- वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया समेकित अनुज्ञप्ति ही है, इसलिये नियमों में निजी भूमि पर उत्खनन पट्टा प्रदान करने के शब्द के स्थान पर समेकित अनुज्ञप्ति का शब्द समाविष्ट किया जाना प्रावधानित किया गया है।
- वर्तमान नियमों में शासकीय विभाग की अनुमति से सरकारी तालाब एवं अन्य संरचनाएँ तथा ग्राम पंचायत की अनुमति से उनके द्वारा निर्मित/संधारित तालाब एवं अन्य संरचनाओं से निकलने वाली कीचड़, गाद पर स्वयं के कार्यों के उपयोग के लिये रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अब निकलने वाली कीचड़, गाद के साथ मिट्टी पर भी रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।
- वर्तमान नियमों में उत्खनन पट्टा के लिये वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय अग्रिम मृत कर राशि एकमुश्त जमा करने का प्रावधान है। अब यह राशि अग्रिम दो किश्तों में पट्टाधारियों से जमा कराए जाने के प्रावधान किये गए हैं।
- अनुसूची-एक, अनुसूची-दो एवं अनुसूची-पाँच में विनिर्दिष्ट खनिजों के शोधों (अनिवार्य भाटक, स्वामित्व, भूतल भाटक, जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि व अन्य देय राशि) के विलंब भुगतान पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान किया जा सकेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में किये गए हैं, जिससे प्रदेश में खदानों के आवंटन में गति लाने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने तथा खनिज राजस्व में वृद्धि के साथ रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे।

'उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047' समारोह

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार कंपनी कार्य-क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 25 से 30 जुलाई, 2022 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव में 'उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047' समारोह आयोजित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि कंपनी कार्य-क्षेत्र के भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल ज़िले में तरावली कला, भैंसाखेड़ी, विदिशा ज़िले में कुरवाई एवं गंज़बासौदा शहर, रायसेन ज़िले में रायसेन एवं सिलवानी शहर, सीहोर ज़िले में सीहोर एवं बुधनी शहर तथा राजगढ़ ज़िले में मंगल भवन एवं पंचायत भवन में समारोह आयोजित किये जाएंगे।

नोट :

- ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर ज़िले में ग्वालियर एवं बिलहाटी, दतिया ज़िले में सेंवढ़ा एवं दतिया शहर, अशोकनगर ज़िले में अशोकनगर शहर एवं मुंगावली गाँव, गुना ज़िले में गुना शहर एवं म्याना टाउन तथा शिवपुरी ज़िले में शिवपुरी शहर एवं करेरा में समारोह होंगे।
- नर्मदापुरम् संभाग के अंतर्गत नर्मदापुरम् ज़िले में इटारसी एवं पचमढ़ी शहर, हरदा ज़िले में हरदा एवं टिमरनी शहर तथा बैतूल ज़िले में नांदू गाँव तहसील घोड़ाडोंगरी एवं आमधाना गाँव तहसील भीमपुर में समारोह आयोजित किये जाएंगे।
- चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर ज़िले में श्योपुर एवं विजयपुर शहर, मुरैना ज़िले में मुरैना टाउन हाल, पंचायत सभागार राजौधा एवं भिंड ज़िले में मेहगाँव शहर एवं फूफ में समारोह होंगे।
- गौरतलब है कि 'उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा, 2047' समारोह में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सेंट्रल पावर सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSE's) के साथ समन्वय कर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों, योजनाओं आदि के प्रदर्शन बैनर, पोस्टर, आडियो विजुअल, नुक्कड़ नाटक आदि ज़िला प्रशासन के माध्यम से समारोह में प्रदर्शित किये जाएंगे।

देश का पशुसखी प्रशिक्षण 'A-HELP' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई को संयुक्त रूप से भोपाल से देश में 'A-HELP' प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। इसमें प्रतीक चिह्न का भी लोकार्पण किया जाएगा।
- कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पंजीकृत स्व-सहायता समूहों की ऐसी महिला सदस्य, जो पशुसखी के रूप में विभिन्न पशुपालन गतिविधियों में सहयोग दे रही हैं, को 'A-HELP' (Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 'A-HELP' समुदाय आधारित महिला कार्यकर्त्ता हैं, जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग देने के साथ पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिये ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं के कान की टैगिंग को चिह्नित कर इनाफ पोर्टल पर दर्ज कराने और पशुधन बीमा आदि कार्यों में सहायता करेंगी।
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग और निचले स्तर तक पशुपालकों को जानकारी उपलब्ध कराने में 'A-HELP' की सहायता ली जा सकेगी। इससे 'A-HELP' को आय का साधन भी उपलब्ध हो सकेगा।

जल जीवन मिशन में 11 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएँ मंज़ूर

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 11 हज़ार 100 करोड़ 72 लाख रुपए की पुनरीक्षित 25 समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश जल निगम इन जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 ज़िलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
- मिशन की जलप्रदाय योजनाओं से 6 हज़ार 261 ग्रामों के 9 लाख 34 हज़ार से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी।

नोट :

- ये योजनाएँ भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगौन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी ज़िले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की ज़रूरत को पूरा करेंगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों से अब तक 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। करीब 5 हज़ार 300 गाँव ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है।
- मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिये जलप्रदाय योजनाओं के कार्य बृहद् स्तर पर चल रहे हैं। इनमें 8 हज़ार से अधिक गाँवों में 70 से 90 प्रतिशत और 16 हज़ार 300 गाँवों के कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्णता की ओर हैं। इसी माह से 6 हज़ार से अधिक गाँवों की पेयजल व्यवस्था के कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को 13वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

मध्य प्रदेश को मिला 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य' का अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें मध्य प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट'का अवार्ड दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2017 के बाद दूसरी बार मध्य प्रदेश को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी।

नोट :

- इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशन मेंशन)' का अवार्ड दिया गया।
- एक अन्य उपलब्धि में नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का अवार्ड राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित फिल्म 'मांडल के बोल'को दिया गया। इस फिल्म को मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा बनाया गया है। यह फिल्म बैगा जनजातीय जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है।
- उल्लेखनीय है कि फिल्ममेकर को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिये प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार फिल्मांकन अनुमति के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा के साथ विभिन्न प्रकार के अनुदान और छूट दी जाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ के लिये अधिकतम 10 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिये 25% अथवा दो करोड़ रुपए एवं टीवी सीरियल एवं वेब सीरीज़ के लिये 25% या एक करोड़ रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिये अधिकतम 40 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
- राज्य के स्थानीय कलाकारों को फिल्म मेकिंग में लेने के लिये अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 30% तक के वित्तीय अनुदान के साथ फिल्म क्रू के लिये पर्यटन विभाग के होटल और रिसॉर्ट में ठहरने पर 40% की छूट प्रदान की जाती है।
- राज्य में फिल्म उद्योग के विकास के लिये फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों के लिये आरक्षित भूमि उपलब्ध है। साथ ही स्थानीय कलाकारों के कौशल वृद्धि के लिये प्रदेश में विभिन्न कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। इन सभी प्रयासों के चलते प्रदेश में 250 से ज़्यादा फिल्म, वेब सीरीज़, सीरियल आदि की शूटिंग हो चुकी है।

बुरहानपुर बना देश का पहला 'हर घर जल' सर्टिफाइड ज़िला

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए बुरहानपुर ज़िला देश का पहला 'हर घर जल' सर्टिफाइड ज़िला बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- बुरहानपुर ज़िले के समस्त 254 ग्रामों में 'हर घर जल'योजना से पानी पहुँचाया जा रहा है। ये ग्राम 'हर घर जल'प्रमाणित हुए हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'जल जीवन मिशन'वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन'(FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- 'जल शक्ति मंत्रालय'के अंतर्गत आने वाले इस मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG–6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत गृह क्रमांक-2 की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक चार ने लगातार 100 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 76.3 फीसदी रहा। यह यूनिट 28 मार्च, 2019 को क्रियाशील हुई थी।
- उल्लेखनीय है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में विद्युत गृह क्रमांक एक में 600-600 मेगावाट की दो और विद्युत गृह क्रमांक दो में 660-660 मेगावाट की दो यूनिट विद्यमान हैं।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक एक ने 233 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
- इसी तरह सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने 186 व 11 ने 202 दिन और संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 210 मेगावाट की यूनिट क्रमांक चार ने 130 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं।

जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को नागर विमानन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने स्पाइसजेट द्वारा जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने कहा कि पिछले एक साल में देश में हवाई सेवाओं में व्यापक विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में जहाँ जुलाई 2021 में प्रति सप्ताह 554 विमानों का आवागमन हो रहा था, वह आँकड़ा अब 980 हो गया है।
- जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों के लिये निर्बाध आवागमन की सुविधा होगी। नई सीधी उड़ान से आम लोगों को यात्रा करने का एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और दोनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।
- उन्होंने कहा कि जबलपुर पहले ही नौ शहरों - बंगलूरू, दिल्ली, बिलासपुर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और भोपाल से जुड़ था। अब इसे 10वें शहर कोलकाता से जोड़ा जा रहा है।
- जबलपुर में विमानों का आवागमन बढ़कर 182 हो गया है। ग्वालियर जुलाई 2021 में 56 विमानों के आवागमन के साथ 4 शहरों से जुड़ा था, अब यह आँकड़ा बढ़कर 100 हो गया है। इसी तरह इंदौर में 308 विमानों का आवागमन हो रहा था, जो बढ़कर 468 हो गया है और अब यह 20 शहरों से जुड़ा है।
- राज्य की राजधानी भोपाल, जिसका जुलाई 2021 में 5 शहरों के साथ हवाई संपर्क था, अब 13 शहरों से जुड़ गया है और इसमें 226 विमानों का आवागमन हो रहा है। खजुराहो भी दिल्ली से जुड़ा है और यहाँ से प्रति सप्ताह 4 उड़ानें संचालित हैं।

तेंदूपत्ता संग्रहण

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110 प्रतिशत ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष लक्ष्य 16 लाख 29 हज़ार मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18 लाख 2 हज़ार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16 लाख 60 हज़ार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ था।

नोट :

- प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 80 ज़िला यूनियन और 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य करवाया जा रहा है। इससे 35 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 50 प्रतिशत संग्राहक अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं और 40 प्रतिशत संग्राहक महिलाएँ हैं।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है।
- प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल, 2022 को हुए वन समितियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर में 500 रुपए की बढ़ोतरी किये जाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 3 हज़ार रुपए प्रति मानक बोरा दर निर्धारित कर दी गई है। इस वृद्धि से संग्राहकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है।
- इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ रुपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके खाते में वितरित किया जाना प्रारंभ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
- तेंदूपत्ता संग्रहण से वर्ष 2020 में 600 करोड़ रुपए और वर्ष 2021 में 843 करोड़ रुपए का विक्रय मूल्य प्राप्त किया गया था।

यूथ महापंचायत

चर्चा में क्यों ?

23 से 24 जुलाई, 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन कन्वेंशन हॉल में पहली यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 23 जुलाई, 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहली यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया था।
- इस पहली यूथ महापंचायत कार्यक्रम में प्रदेश के सभी ज़िलों के युवाओं ने ऑनलाइन सहभागिता की।
- राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में 52 ज़िलों से चयनित छह-छह युवा तथा एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के कैडेट्स और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए।
- दो दिवसीय यूथ महापंचायत में पर्यावरण और युवा, नेक्स्ट जेन. स्टार्टअप्स, मेरा एमपी-मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन तथा युवा और लोकतंत्र विषय पर सत्र आयोजित हुए।

जल जीवन मिशन में 1142 जल-प्रदाय योजनाएँ और शामिल हुईं

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल-जल प्रदाय के लिये 608 करोड़ 55 लाख 87 हज़ार रुपए की लागत वाली 1142 ग्रामों के लिये एकल जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की।

प्रमुख बिंदु

- जल-प्रदाय की इन एकल ग्राम योजनाओं में रेट्रोफिटिंग का कार्य भी शामिल है।
- इन स्वीकृत जल-प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा।
- प्रस्तावित जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन ज़िलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 51 लाख 20 हज़ार ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी तरह 5 हज़ार 382 ग्राम ऐसे हैं, जिनके सभी परिवारों को पेयजल मुहैया करवाया गया है।
- मिशन में 23 हज़ार 700 से अधिक ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य 70 से 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और 7 हज़ार 300 से अधिक ग्रामों के लिये समूह और एकल जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य शुरू किया जा रहा है।

नोट :

प्रदेश का पहला 200 MVA ट्रांसफार्मर दमोह में ऊर्जीकृत

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 220 KV सब स्टेशन दमोह में 160 MVA क्षमता के स्थान पर विशेष डिजाइन से तैयार किया गया प्रदेश का पहला 200 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर उर्जीकृत किया।

प्रमुख बिंदु

- ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता प्रोक्योरमेंट जबलपुर इंजीनियर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश में परंपरागत 120 MVA या 160 MVA के पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाते थे। इनके स्थान पर 200 MVA क्षमता का यह पहला पावर ट्रांसफार्मर है।
- दमोह में इस ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से ज़िले के हट्टा, तेजगढ़, बटियागढ़ तथा पटेरा के 132 KV सब-स्टेशनों से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं के अलावा सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ ज़िले के सब-स्टेशनों को भी फायदा होगा। यहाँ किसी इमरजेंसी में 220 KV सब-स्टेशन दमोह से सप्लाई की जा सकेगी।
- गौरतलब है कि दमोह पूर्व में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रमुख लोड सेंटर हुआ करता था। दमोह से सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, बिजावर, बीना आदि क्षेत्रों सहित अनेक सीमेंट फैक्ट्रियों तथा रेलवे को विद्युत आपूर्ति की जाती थी।
- दमोह ज़िले में 16 जून, 1967 को पहला अति उच्च दाब सब-स्टेशन5 MVA क्षमता के साथ प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में दमोह ज़िले में 220 KV एक तथा 132 KV के पाँच सब-स्टेशनों के साथ विद्युत आपूर्ति की जाती है।
- दमोह में 220 KV साइड की 360 MVA तथा 132 KV साइड की 530 MVA की मज़बूत ट्रांसफॉरमेशन क्षमता है, जो ज़िले के उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता की निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम है।

राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को 'बेस्ट एंप्लायर ब्रांड अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल को 'बेस्ट एंप्लायर ब्रांड अवार्ड 2022' से पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड इंदर सिंह परमार को राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के निदेशक प्रभातराज तिवारी ने सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर इस उपलब्धि से अवगत कराया।
- निदेशक प्रभातराज तिवारी ने बताया कि वर्ल्ड एच.आर.डी कॉन्ग्रेस के डायरेक्टर डॉ. आर.एल भाटिया द्वारा यह अवार्ड इंदौर के मेरियट होटल में दिया गया है।
- राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को ज्यूरी द्वारा चुना गया है। बोर्ड ने पिछले वर्षों में नई योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रशासन एवं हितग्राही सेवाओं में सबसे उच्च स्थान बनाया है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य मुत्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विगत समय में किये गए नवाचारों से काफी प्रसिद्धि पाई है। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2018 में निगम, मंडलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा दिया गया था। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2022 में ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है।

प्रदेश को मिला नया कर्माझिरी अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को राज्य शासन द्वारा पेंच टाइगर रिज़र्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझिरी अभयारण्य का गठन किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि नवगठित कर्माझिरी अभयारण्य में सिवनी ज़िले के 420 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इसके गठन से टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन को मज़बूती मिलेगी और शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्य-प्राणियों को अतिरिक्त रहवास स्थल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, प्रदेश में वन्य-प्राणी बहुल क्षेत्र को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र के रकबे में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 24 अभयारण्य हैं। शिवपुरी के करेरा अभयारण्य को डिनोटिफाई किया गया है। इस प्रकार कर्माझिरी अभयारण्य के गठन के बाद संख्या कुल 24 ही रहेगी।
- राज्य शासन ने भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के बाद एक और महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए शिवपुरी ज़िले के करेरा में 21 वर्ग किमी. क्षेत्र में बने वन्य-प्राणी अभयारण्य को समाप्त कर दिया है। इससे इस क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिये किया गया था। इसमें केवल राजस्व और निजी भूमि शामिल थी। अभयारण्य की अधिसूचना के बाद से अधिसूचना में शामिल भूमि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

शिवपुरी की सांख्य सागर झील रामसर साइट में शामिल

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को देश में नई घोषित पाँच रामसर साइट्स में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को भी शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश को दो दशक बाद दूसरी रामसर साइट मिली है। इससे पहले भोपाल के बड़ा तालाब (भोजताल) को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है।
- गौरतलब है कि प्रदेश की 3 आर्द्रभूमि इंदौर के सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर तथा सांख्य सागर को रामसर साइट के रूप में घोषित करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।
- केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के पाँच नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किये हैं, जिनमें तमिलनाडु में तीन आर्द्रभूमि स्थल (करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव), मिज़ोरम में एक (पाला आर्द्रभूमि) और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल (सांख्य सागर) शामिल हैं। इस प्रकार, देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि झील संरक्षण के संबंध में ईरान के रामसर नगर में वर्ष 1971 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड साइट्स की सूची संधारित की जाती है।

वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इंडिया अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (पर्यटन और संस्कृति) एवं प्रबंध संचालक टूरिज़्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी भोपाल करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ADTOI-MP चेप्टर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।

नोट :

- 30 अगस्त, 2022 से शुरू होने वाले ये कार्यक्रम 10 सितंबर, 2022 तक चलेंगे। इसके अंतर्गत यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्राँस सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों वाली एक आईसीआरटी टीम मध्य प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों का दौरा करेगी। टीम का नेतृत्व आईसीआरटी के संस्थापक निदेशक और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पार्टनशिप के प्रबंध निदेशक डॉ. हेरोल्ड गुडविन करेंगे।
- यह टीम प्रदेश के समृद्ध विरासत स्थलों और ग्रामीण पर्यटन के विकसित गाँवों का अवलोकन करेगी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में ग्राम-स्टे, स्थानीय भ्रमण, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेगी।
- यह टीम मंडला में प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट), प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल सोवेनियर एवं ओरछा में प्रोजेक्ट हमसफर की समीक्षा भी करेगी।
- उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म (ICRT) ऐसे प्रबुद्धजनों का एक नेटवर्क है, जो केपटाउन घोषणा का समर्थन करते हैं। इसमें कई सहयोगी संगठन और संबद्ध केंद्र हैं। इसकी स्थापना 2002 में हेरोल्ड गुडविन द्वारा पर्यटन गंतव्यों में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और 2002 के केप टाउन घोषणा के परिणामस्वरूप की गई थी।
- आईसीआरटी नेटवर्क के सदस्य रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवधारणा को विकसित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म द्वारा वर्ष 2004 से वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म अवार्ड की शुरुआत की गई।
- इस अवार्ड का उद्देश्य विश्व में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा देना एवं संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे अच्छे कार्यों के संबंध में जागरूक करना है।
- वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 10 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। अभी तक यह अवार्ड कार्यक्रम लंदन में डब्ल्यू.टी.एम. में होता था। पहली बार भारत एवं सब कॉन्टिनेंट का अवार्ड लंदन से बाहर भोपाल में होने जा रहा है।
- इस अवार्ड में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया एवं नेपाल आदि देश हिस्सा लेंगे। अवार्ड के विजेता का अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा चयन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष डॉ. हेराल्ड गुडविन होंगे।
- इस अवार्ड की प्रमुख श्रेणियाँ निम्न हैं-
  - डिकार्बनाइजिंग ट्रेवल एंड टूरिज्म
  - सस्टेनिंग एम्पालाइज एंड कम्युनिटी थ्रू पेंडेमिक
  - डेस्टिनेशन बिल्डिंग बैक बेटर पोस्ट कोविड
  - इंक्रीज डायवरसिटी इन टूरिज्म, हाउ इंक्लूसिव इज अवर इंडस्ट्रीज
  - रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट इन द इनवायरमेंट
  - ग्रोइंग द लोकल इकोनॉमिक बेनीफिट
  - एक्सेस फॉर द डिफ्रेंटली एबल्ड एस ट्रेवलर्स, इम्पलाइज एंड हॉलीडे मेकर्स
  - इंक्रीज टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेचुरल हेरीटेज एंड बायो डायवर्सिटी
  - कंजरविंग वाटर एंड इंप्रूविंग वाटर सिक्योरिटी एंड सप्लाई फार नेबर्स
  - कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल हेरीटेज

एमपीकिसान ऐप

चर्चा में क्यों ?

28, जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार' में अब किसान अपनी फसल की जानकारी एमपीकिसान ऐप (MPKISAN App) के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा।
- किसान अपनी फसल की जानकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।

नोट :

- 'मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार'में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान ऐप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।
- किसान इस ऐप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा, दावा ऑपत्ति आप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं।
- खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी।
- किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोई गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

करोंद मंडी में बनेगा एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह के भोपाल की करोंद मंडी परिसर में फूलों के लिये मध्य प्रदेश के पहले एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि फूलों की खेती करने वाले किसानों को एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम के बन जाने से अपनी फसल का वाज़िब दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- मंडी में आए किसानों को अच्छे दाम नहीं मिलने की स्थिति में फूलों को रखने की सुविधा मिल जाएगी और अच्छे दाम मिलने पर किसान उन्हें बेच सकेंगे। इससे किसान बिचौलियों के शोषण से भी मुक्त होंगे और फूलों की खेती लाभ का व्यवसाय बनेगी।
- राज्य मंत्री ने कहा कि भोपाल में 180.51 लाख रुपए लागत से यह एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा। प्रदेश का यह पहला डोम है। इसको विभाग की एमआईडीएच योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार एयर वेंटीलेटेड फ्लावर डोम बनाए जाएंगे।

'गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग'

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को हैदराबाद में 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को 'गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग'मिला है।

प्रमुख बिंदु

- इनोवेशन इन एजुकेशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया।
- दीपक सिंह ने कहा कि प्रदेश को यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। इस प्रोत्साहन से भविष्य में भी प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेगा।
- विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिये व्यावसायिक विषय, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटेशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को रोज़गार से जोड़ने का कार्य किया गया है।
- विदित है कि मध्य प्रदेश में सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में डिजी लॉकर की व्यवस्था उपलब्ध है। इससे छात्रों को कहीं भी अपनी अंकसूची, उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन आदि प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो सकेंगे।
- विभाग द्वारा नवाचार, डिजिटल इनिशिएटिव्स, एकीकृत पोर्टल का निर्माण, ऑनलाइन प्रवेश, ई-शिक्षा, ई-कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल क्लासेज और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण कार्य किये जा रहे हैं।

नोट :

ज़िलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई ज़िलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में नाबार्ड की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
- यह मध्य प्रदेश की यह पहली वित्तीय समावेशन रिपोर्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस (एग्पा) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट प्रदेश के विकास में मार्गदर्शन का काम करेगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश को वित्तीय समावेशन के लिये 5-सी एप्रोच (कंटेंट, केपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलेबरेशन) को अपनाना चाहिये तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- संस्थान की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.वी. रश्मि ने बताया कि वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिये तैयार किया गया है। सूचकांकों में राज्य में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति के मामले तथा मांग और आपूर्ति संकेतकों को शामिल किया गया है।
- वित्तीय समावेशन के स्तर का आकलन करने के लिये वित्तीय सेवाओं के उपयोग में पहुँच, उपयोग के आयामों और बाधाओं का उपयोग किया गया है।
- सूचकांक में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर शून्य से एक का स्कोर दिया गया है। राज्य ने पिछले 2 वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन स्कोर में 0.238 से 0.283 तक सुधार किया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सुविधा में शाजापुर, मंडला, बड़वानी, भिंड, मुरैना, सतना, दतिया जैसे 16 ज़िले पिछड़े हुए हैं। इनमें जनजाति बहुल ज़िले ज़्यादा हैं, जबकि भोपाल, इंदौर, रायसेन, धार सहित 17 ज़िलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है।
- बैंक में खाता खुलवाने सहित वित्तीय लेन-देन, एटीएम का उपयोग और डिजिटल बैंकिंग की दृष्टि से ज़िलों को तीन श्रेणी (उच्च वित्तीय समावेशन ज़िले, मध्यम वित्तीय समावेशन ज़िले और कम वित्तीय समावेशन ज़िले) में वर्गीकृत कर रिपोर्ट तैयार की गई है।
- इस रिपोर्ट का औसत सूचकांक 0.268 रखा गया है। 0.640 के सूचकांक के साथ भोपाल ज़िले ने वित्तीय समावेशन सूचकांक में अग्रणी स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में 17 ज़िले हैं, जिन्हें 0.319 से 0.640 अंक हासिल हुए हैं।
- इस अध्ययन में नीति आयोग ने चिह्नित आकांक्षी ज़िले (विदिशा, राजगढ़, दमोह, गुना, छतरपुर, खंडवा, बड़वानी और सिंगरौली) की स्थिति भी प्रस्तुत की है।
- उच्च वित्तीय समावेशन ज़िले : भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, हरदा, धार, जबलपुर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, नीमच, देवास, रायसेन, छिंदवाड़ा, झाबुआ, नरसिंहपुर और राजगढ़।
- मध्यम वित्तीय समावेशन ज़िले : शहडोल, बालाघाट, दमोह, सागर, मंदसौर, कटनी, पन्ना, सीधी, छतरपुर, अनूपपुर, बैतूल, विदिशा, उमरिया, सिवनी, अशोकनगर, गुना और खरगौन ज़िले शामिल हैं। इन ज़िलों ने 0.229 से 0.316 अंक प्राप्त किये हैं।
- कम वित्तीय समावेशन ज़िले : शाजापुर, मंडला, बड़वानी, खंडवा, दतिया, डिंडोरी, सतना, टीकमगढ़, श्योपुर, आलीराजपुर, बुरहानपुर, रीवा, शिवपुरी, सिंगरौली, भिंड और मुरैना ज़िले शामिल हैं। इन ज़िलों ने 0.101 से 0.222 अंक प्राप्त किये हैं।
- अध्ययन में बताया गया है कि बैंक अधिकारियों से बातचीत में अनिच्छा के चलते जनजातीय समाज के लोग बैंक जाने से बचते हैं। ग्राहक सेवा केंद्रों से भी उनके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं।

आईटीसीटीए कॉन्क्लेव चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश ने जीते 2 अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड ट्रैवल अवार्ड के 8वें संस्करण में मध्य प्रदेश टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर के दो अवार्ड जीते।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पर्यटन को अपने फेयर्स फेस्टिवल्स को बढ़ावा देने एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को वेल मेंटेंड होटल्स के लिये अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से उप संचालक युवराज पडोले एवं महाप्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अवार्ड प्राप्त किये।
- उप संचालक (आयोजन और विपणन) टूरिज्म बोर्ड युवराज पडोले ने पीपीटी से प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों एवं टूरिस्ट आकर्षण के अन्य पहलुओं का संक्षिप्त विवरण दिया।
- उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वन्य-जीव सफारी, प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक गतिविधियाँ, कैम्पिंग, वाटर स्पोर्ट, स्वादिष्ट व्यंजन, विरासत स्थल, जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, वेलनेस तथा माइंडफुल पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :